सीएमपीडीआई की विशिष्ट/प्रमुख उपलिब्धयां (2020–21)

- 26 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से 304 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल कर विस्तृत गवेषण के माध्यम से लगभग 13.1 बिलियन टन कोयला संसाधन को प्रमाणित श्रेणी में लाया गया जो अपने स्थापना काल से सीएमपीडीआई द्वारा एक वर्ष में अब तक का आकलित किया गया सबसे अधिक कोयला संसाधन है। यह वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में लगभग 69 प्रतिशत की वृद्धि है।
- इसके अतिरिक्त, 4 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के जरिए 134 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को शामिल कर प्रोमोशनल (रिजनल) गवेषण के जरिए 1.33 बिलियन टन (इंडीकेटेड एवं इफर्ड कैटेगरी) नए संशाधन का आकलन किया गया ।
- सीएमपीडीआई ने 11 लाख मीटर एमओयू लक्ष्य की तुलना में 12.48 लाख मीटर ड्रिलिंग की है जिसमें 0.44 लाख मीटर प्रोमोशनल गवेषण शामिल है। वर्ष 2020-21 के दौरान कोयला मंत्रालय के सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के प्रोमोशनल एक्सप्लोरेशन के तहत विभिन्न एजेंसियों के द्वारा 1.00 लाख मीटर लक्ष्य की तुलना में 1.35 लाख मीटर (सीएमपीडीआई द्वारा 0.44 लाख मीटर सहित) ड्रिलिंग की गई।
- विवेच्य वर्ष के दौरान, गैर-सीआईएल ब्लॉकों में लगभग 6.45 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई। 12 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के जरिए 160.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल कर लगभग 5.27 बिलियन टन कोयला संसाधन प्रमाणित श्रेणी में लाया गया ।
- इसके अतिरिक्त, गत वर्ष के 28.26 लाइन किलोमीटर की तुलना में 945 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2020-21 के दौरान 295.37 लाइन किलोमीटर 2डी/3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (सिस्मिक सर्वे) किया गया।
- सीएमपीडीआई ने कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र में विस्तृत गवेषण के तहत 117 ब्लॉकों/खानों तथा क्षेत्रीय गवेषण के तहत 36 ब्लॉकों में गवेषणात्मक ड्रिलिंग की।
- मध्य प्रदेश के सोहागपुर कोलफील्ड क्षेत्र के दो ब्लॉकों यथा सेन्दुरी ब्लॉक तथा निगवानी बकेली-ए में मेसर्स एसईआरसीईएल, फ्रांस से आयातित वाइब्रोसिस के द्वारा 2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (सिस्मिक सर्वे) किया जा रहा है और लगभग 77.46 लाइन किलोमीटर भूकम्पीय (सिस्मक) डाटा प्राप्त किया गया।
- गवेषण की गति को बढ़ाने के लिए 270 करोड़ की कुल लागत पर 330 किलो मीटर क्षेत्र वाले 10 ब्लॉकों में 2 बोरहोल प्रति वर्ग कि0 मी0 की दर से 2डी सिस्मक सर्वे कार्य को आउट सोर्स किया गया है।
- गैर कोरिंग ड्रिलिंग के पूरक के रूप में विभागीय तौर पर लगभग 2.01 लाख मीटर भूभौतिकी लॉगिंग किया गया।

- भारत के खनन क्षेत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के लिए जल भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीजीडब्ल्यूए द्वारा सीएमपीडीआई के जल भूविज्ञान (हाइड्रोजियोलॉजी) विभाग को ''ग्राउंडवाटर प्रोफेशनल्स'' के रूप में मान्यता दी गई है। क्यूसीआई-एनएबीईटी द्वारा जीडब्ल्यूसीओ (भूजल परामर्शदाता संगठन) के रूप में मान्यता की प्रक्रिया चल रही है।
- वीएसटीपीएस, सिंगरौली, मध्य प्रदेश द्वारा गोरबी खान रीक्ति में फ्लाई एश डम्पिंग के प्रभाव का मूल्यांकन के लिए जल भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ-साथ एक्वीफर परफॉरमेंस टेस्ट किया गया।
- बीसीसीएल के क्लस्टर-XVI खानों में बोरवेलों द्वारा दामोदर नदी का परमीएब्लिटी तथा सीपेज के लिए जल भूवैज्ञानिक अध्ययन किया गया ।
- वर्ष 2020-21 के दौरान भूवैज्ञानिक रिपोर्ट/परियोजना रिपोर्ट/ढाल स्थायित्व रिपोर्ट/ जलापूर्ति योजना के लिए 148 भूवैज्ञानिक अध्ययन तैयार किए गए।
- ईएमपी तैयार करने के लिए 12 खनन परियोजनाओं/खानों के भूवैज्ञानिक अध्ययन किए गए । जल भूविज्ञान विभाग कोल इंडिया लिमिटेड की एमओईएफ एंड सीसी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के लिए भूमिगत जल सतह तथा गुणवत्ता निगरानी का कार्य भी कर रहा है।
- भारत में अनुमानित कोयलाधारक क्षेत्र की पहचान करने के लिए अगस्त, 2020 में जीएसआई के साथ सीएमपीडीआई द्वारा संयुक्त अभ्यास किया गया जिसमें कुल 43 गोंदवाना कोलफील्डों तथा 19 टर्शियरी कोलफील्डों का अध्ययन किया गया।
- गोंदवाना कोलफील्ड का बेसीन वाला कुल क्षेत्र लगभग 65574 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से कुल 32761 वर्ग किलोमीटर कोयलाधारक क्षेत्र होने का पूर्वानुमान लगाया गया है जो पहले के आकलन 19400 वर्ग किलोमीटर से 69 प्रतिशत अधिक है। कुल रिजनल एक्सप्लोरेशन क्षेत्र लगभग 18636 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से 13256 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रिजनल एक्सप्लोरेशन के लिए उपलब्ध है। लगभग 300 गैर कोकिंग कोयला ब्लॉक तथा 24 कोकिंग कोयला ब्लॉक वाले इसे अगवेषित क्षेत्र में भावी गवेषण के लिए नए ब्लॉकों की पहचान कर ली गई है।
- टर्शियरी कोलफील्ड्स का कुल बेसिन वाला क्षेत्र 1343 वर्ग किलोमीटर आंका गया है, जिसमें से लगभग 945 वर्ग किलोमीटर कोयलाधारक क्षेत्र होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। कुल रिजनल एक्सप्लोरेशन क्षेत्र लगभग 456 वर्ग किमी है । पूर्वोत्तर क्षेत्र में गवेषण के लिए 91 नए कोयला ब्लॉकों की पहचान की गई है।
- वर्ष 2021-22 और इससे आगे के वर्षों के लिए गवेषण शुरू करने हेतु 24 नये कोकिंग कोयला ब्लॉकों और 5 नए अच्छे गुणवत्ता वाले नन-कोकिंग कोल ब्लॉकों की पहचान की गई है।

- कोकिंग कोयला ब्लॉकों के जियो-माइनिंग संभाव्यता पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है और इस पर रिपोर्ट तैयार कर सौंप दी गयी है।
- सभी सूचीबद्ध ब्लॉकों (01.04.2020 तक 957) के लिए डीएसएस और ईएसजेड विश्लेषण किया गया और इसे कोयला ब्लॉकों की निलामी करने हेतु निर्णय लेने के लिए कोयला मंत्रालय को उपलब्ध करा दिया गया है। कोयला ब्लॉकों की निलामी के लिए लगभग 100 कोयला ब्लॉकों का खान सारांश (माइन समरी) तैयार किया गया है।
- प्रति वर्ष लगभग 169 एमटी प्रतिवर्ष क्षमता वृद्धि वाली 33 परियोजना रिपोर्टें तैयार की गईं।
- 40 पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं (31 फार्म-1 सहित) तैयार की गईं।
- वर्ष 2020-21 के दौरान 14 अनुसंधान परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है, जो विगत 5 वर्षों के दौरान सर्वाधिक है तथा 6 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है। वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए 22.2 करोड़ रूपये का कोष वितरित किया गया।
- आसपास के आवसों तथा महत्वपूर्ण इमारतों को बचाने तथा बंद पड़े कोयला को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न खानों के लिए नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपन अध्ययन पर 9 रिपोर्टें तैयार की गईं।
- पूरे वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की खानों में प्रयोग में लाए जा रहे बल्क/काट्रीज विस्फोटकों की रैण्डम सेम्पलिंग तथा परीक्षण किया गया तथा इसके बारे में 56 रिपोर्टें तैयार की गयी। इसके अतिरिक्त, विस्फोटन पारामीटर/पावडर फैक्टर के अनुकूलन से संबंधित 36 रिपोर्टें भी तैयार की गयीं।
- एससीसीएल और एनएलसी की खदानों में इस्तेमाल होने वाले बल्क/कार्ट्रिज विस्फोटकों और एक्सेसरीज का रैंडम सैंपलिंग और परीक्षण पूरे साल किया गया और इस संबंध में 12 रिपोर्ट तैयार की गईं।
- सीएमपीडीआई हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा पर आधारित नियमित आधार पर कोल इंडिया लिमिटेड की खानों की भूमि पुनरूद्धार मॉनिटरिंग का काम करते आ रहा है। वर्ष 2020-21 में कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों में 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) से अधिक उत्पादन करने वाली कोटि की 51 खुली खान परियोजनाओं तथा 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) से कम उत्पादन करने वाली 46 खुली खान परियोजनाओं, 09 क्लस्टर्स तथा 5 भूमिगत खानों को शामिल कर कुल 111 परियोजनाओं की भूमि पुनरूद्धार मॉनिटरिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
- कोलफील्ड क्षेत्रों में भू-उपयोग/वृक्षारोपण पर खनन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा पर आधारित कोल इंडिया लिमिटेड की वनस्पति आच्छादन मापन का काम नियमित रूप से कर रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान 7 कोलफील्डों यथा

उमरेर एवं पेंच कन्हान कोलफील्ड्स (डब्ल्यूसीएल), इब वैली कोलफील्ड्स (एमसीएल), मांड रायगढ़ एवं सोहागपुर कोलफील्ड्स (एसईसीएल) का वनस्पति आच्छादन मानचित्रण का कार्य सफलतापूर्वक कर लिया गया है।

- 2020-21 के दौरान 6 ओपेनकास्ट परियोजनाओं के उपग्रह डेटा के आधार पर कोर और बफर जोन का भूमि उपयोग/कवर मैपिंग किया गया। एमओईएफ और सीसी के अनुपालन के लिए 2020-21 के दौरान एसईसीएल की 8 भूमिगत परियोजनाओं के लीजहोल्ड क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग कवर मैप पूरा किया गया । इसके अलावा, मेसर्स टाटा स्टील के वेस्ट बोकारो कोलियरी के कोर और बफर जोन के लैंड यूज़/कवर मैपिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है।

- नई प्रौद्योगिकी अपनाने में, सीएमपीडीआई ने सर्वेक्षण और मैपिंग के लिए ड्रोन खरीदे हैं। पहले ड्रोन की आपूर्ति दिसम्बर, 2020 में की गयी जो अत्याधुनिक लिडार ऑप्टिकल और थर्मल सेंसर से लैस है। दूसरे ड्रोन की आपूर्ति भी मार्च 2021 के अंतिम सप्ताह में की गई । भारत में ड्रोन को उड़ाने/ऑपरेट करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुमति की आवश्यकता होती है। कोल इंडिया लिमिटेड के कोलफील्ड क्षेत्रों में ड्रोन संचालित करने के लिए सीएमपीडीआई को सशर्त छूट दी गई है।

- कोयला उद्योग में ड्रोन के प्रयोग में तेजी लाने के लिए, सीएमपीडीआई ने कोयला उद्योग में विभिन्न अनुप्रयोगों में इसकी प्रभावशीलता स्थापित करने के लिए ड्रोन सेवा प्रदाताओं को काम पर रखने के लिए कार्रवाई की है। एनसीएल के लिए खुली निविदा के लिए पहला काम मार्च, 2021 में दिया गया है। अन्य सहायक कंपनियों के लिए जल्द ही निविदाएं जारी की जाएंगी।

- सीएमपीडीआई ने मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना के कटरा-बनिहाल खंड में 4 सुरंगों में 18 चरणों में जाइरो-अजीमुथ के निर्धारण के लिए सफलतापूर्वक जाइरोस्कोपिक सर्वेक्षण किया है। यह जम्मू और कश्मीर में भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित रेलवे परियोजना है। यह सर्वेक्षण जनवरी, 2021 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था।

- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के कनिहा और हिंगुला ओसीपी के विस्तार क्षेत्रों में उच्च रिजॉल्यूशन उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके अनधिकृत संरचनाओं का पता लगाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

- सीआईएल ने मशीनीकृत कन्वेयर सिस्टम और रेलवे रेक में कम्प्यूटरीकृत लोडिंग जैसे वैकल्पिक परिवहन विधियों को नियोजित करके कोयला हैंडलिंग दक्षता बढ़ाने के लिए 4 एमटीपीए या उससे अधिक की उत्पादन क्षमता वाली कोयला खदानों में 35 एफएमसी परियोजनाएं (चरण-I) शुरू की हैं। सीआईएल की विभिन्न सहायक कम्पनियों की सभी 35 एफएमसी परियोजनाओं के लिए सीएमपीडीआई द्वारा निविदा दस्तावेज तैयार किए गए और सफलतापूर्वक निविदा जारी किया गया ।

- बीसीसीएल के दुग्धा वाशरी में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र पर एक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई ।
- सीएमपीडीआई (मुख्यालय) को भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता द्वारा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) आईएसओ-37001, 2016 से मान्यता दे दी गई। सीएमपीडीआई यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा सार्वजनिक उपक्रम है।
- सीएमपीडीआई द्वारा तैयार सीसीएल के कोटरे बसंतपुर (5 एमटीवाई) के लिए पीआर, सीआईएल में एमडीओ मोड में प्रदान की जाने वाली पहली परियोजना है। सीएमपीडीआई ने एमडीओ को सियारमल ओसीपी (50एमटीवाई) के विकास और संचालन अनुबंध को सफलतापूर्वक प्रदान करने में एमसीएल की भी सहायता की।
- पीएम 10, पीएम 2.5, सीओ जैसे वायु प्रदूषकों की वास्तविक समय निगरानी (रीयल टाइम मॉनिटरिंग) के लिए सीएमपीडीआई मुख्यालय में निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) स्थापित की गई है।
- सीआईएल के सहयोग से सीआईएल के लिए काफी टेबल बुक तैयार की गई । कोयला मंत्रालय के लिए कोयला क्षेत्र (सीआईएल, एससीसीएल, एनएलसीआईएल और एनटीपीसी सहित) के लिए पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट भी तैयार की गई ।
- भारत में कोयला क्षेत्र के लिए खान जल उपयोग रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें स्वयं के उपयोग तथा आस-पास के समुदाय द्वारा घरेलू और सिंचाई के लिए उपलब्ध खदान के पानी पर प्रकाश डाला गया था।
- ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट की ऑनलाइन पुनरीक्षण के लिए पीयर रिव्यू सिस्टम विकसित किया गया है तथा यह काम कर रहा है।
- सीआईएल में पहली बार एनसीएल के अस्पताल तरल अपशिष्ट प्रबंधन की योजना तैयार की गई ।
- आरआई-1, आसनसोल के पर्यावरण प्रयोगशाला को दिनांक 02.10.2020 को एनएबीएल एक्रिडिशन प्रदान किया गया जो 2 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। यह सीएमपीडीआई में पहली प्रयोगशाला है जिसे ध्वनि निगरानी और 24 घंटे (दिन-रात) ध्वनि स्तर की निगरानी करने के लिए मान्यता प्रदान की गई।
- सीएमपीडीआई ने अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देने के लिए कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में एसएंडटी अनुसंधान के लिए एक वेबसाइट (https://scienceandtech.cmpdi.co.in) डिजाइन और विकसित की है जो पूर्ण और चल रही अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करती है और विभिन्न रूपों के साथ कोयला अनुसंधान परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश देती है ताकि कोई अपेक्षित तरीके से प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके। इसमें पारदर्शिता रखने और परियोजनाओं

की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पूर्ण परियोजनाओं और चल रही अनुसंधान परियोजनाओं की सूची और परिणाम भी उपलब्ध है।

- कोयला मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार, कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रों में भविष्य के अनुसंधान के लिए नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है। वर्तमान आवश्यकता और कोयला उद्योग के जटिल कार्यों को संबोधित करने के लिए प्रासंगिक कुछ नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, उन्नत प्रौद्योगिकी के नवाचार और स्वदेशीकरण (आत्म-निर्भर भारत), कचरे से धन का निर्माण, आदि। भारत के सभी प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बीच थ्रस्ट एरिया के व्यापक प्रसार के परिणामस्वरूप् नए विषयों पर शोध प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए है। 2020-21 के दौरान कुल 75 नई परियोजनाओं की प्राप्ति हुई है।
- ''नॉर्थ ईस्ट रिजन (एनईआर) कोलफील्ड, इंडिया से कोयला एवं लिग्नाइट संस्तर में रेयर अर्थ एलिमेंट का मूल्यांकन तथा अन्य आर्थिक संसाधन तथा एसिड माइन ड्रेनेज का गुण-निर्धारण एवं इसके प्रदूषण नियंत्रण'' नामक एक एसएंडटी परियोजना का शुरूआत पंजाब टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ तथा ड्यूक यूनिवर्सिटी, यूएसए के सहयोग से की गयी है।
- व्यावसायिक खनन की पहली किश्त के 38 कोयला ब्लॉक तथा व्यावसायिक खनन की दूसरी किश्त के लिए 67 कोयला ब्लॉक हेतु माइन डोजियर एवं माइन समरी (मैप एवं कार्डिनल प्वाइंट सहित) तैयार कर कोयला मंत्रालय को सौंप दी गई है।
- सीएमपीडीआई ने भूमिगत खानों, खुली खदानों, बंद खदानों और क्षेत्रीय रूप से गवेषित (खोजे गए) ओपनकास्ट कोयला ब्लॉकों के लिए एमडीओ मोड पर मॉडल बोली दस्तावेजों के निर्माण और अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- **सीआईएल में कोल बेड मिथेन (सीबीएम)/कोल माइन मिथेन (सीएमएम) का विकास:**
  - ✓ सीएमपीडीआई ईसीएल, बीसीसीएल और एसईसीएल के लिए उनके लीजहोल्ड क्षेत्रों में सीबीएम के विकास के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है।
  - ✓ 15 मई, 2020 को रानीगंज सीबीएम ब्लॉक और झरिया सीबीएम ब्लॉक-1 के लिए निविदाएं मंगाई गई थीं लेकिन कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। सीएमपीडीआई द्वारा बोलीदाताओं के सुझावों को शामिल करने के बाद संशोधित बोली दस्तावेज तैयार किया गया था और 27 अक्टूबर, 2020 को सीआईएल एफडी द्वारा अनुमोदित किया गया था। रानीगंज सीबीएम ब्लॉक और झरिया सीबीएम ब्लॉक-1 के लिए वैश्विक निविदाएं 30 अक्टूबर, 2020 को फिर से जारी की गई थी। परन्तु रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। झरिया सीबीएम ब्लॉक-1 के लिए एक बोली प्राप्त हुई थी जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीबीएम डेवलपर के चयन के लिए सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक के लिए निविदा 12.12.2020 को जारी की गई थी। बोली 05.02.2021 को खोली गई थी। कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

- **ओएनजीसी-सीआईएल संयुक्त उद्यम के तहत सीबीएम परियोजना:**
  झरिया सीबीएम ब्लॉक ने 05.01.2021 को पहले विकास कुएं के स्पूडिंग के साथ वाणिज्यिक चरण में प्रवेश किया।

- **छोड़े गए/छोड़ने वाले सीबीएम ब्लॉकों के साथ कोयला ब्लॉकों के ओवरलैपिंग मुद्दे**:

  डीजीएच द्वारा नीलामी/पुन: नीलामी के लिए प्रस्तावित सीबीएम ब्लॉकों को छोड़े गए/छोड़ने के तहत कोयला ब्लॉकों के ओवरलैप मुद्दों का अध्ययन करने के लिए डीजीएच और सीएमपीडीआई के अधिकारियों से एक संयुक्त टीम का गठन किया गया । किए गए संयुक्त अभ्यास में, सीबीएम ब्लॉकों और कोयला ब्लॉक की सीमाओं को फिर से तराश कर 17 त्याग किए गए/छोड़े जाने वाले सीबीएम ब्लॉकों के साथ 108 कोयला ब्लॉकों को ओवरलैपिंग (ओवरलैप क्षेत्र ≈ 1218 वर्ग किमी) से मुक्त कर दिया गया है।

- **सीआईएल के बाहर परामर्शी सेवाएं:**
  - ✓ सीएमपीडीआई ने 2020-21 के दौरान 23 संगठनों से 20.15 करोड़ रूपये की सेवाएं प्राप्त की हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी संगठन के साथ साथ कोयला मंत्रालय एवं निजी कंपनियां भी शामिल हैं।
  - ✓ 18 संगठनों के लिए 68.94 करोड़ रूपये का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। कुछ प्रमुख ग्राहक एनटीपीसी लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, जेएसब्ल्यू स्टील लिमिटेड, सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड आदि है।
  - ✓ प्राप्त किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं:- मेसर्स ईएमआईएल माईन्स एंड मिनिरल रिर्सोसेज लिमिटेड के बंधा कोयला ब्लॉक के लिए खनन योजना (माइन क्लोजर प्लान सहित) तथा परियोजना रिपोर्ट की तैयारी; मेसर्स एससीसीएल के केजीएम क्षेत्र में ईपीसी मोड पर वीके 7 सीएचपी की स्थापना के लिए परामर्शी सेवा देना; मेसर्स एनएमडीसी की टोकीसूद खुली खान परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी; मेसर्स एससीसीएल के 6 सीएचपी क्षेत्र में ईपीसी मोड पर आरजीओसी3 कोल हैंडलिंग प्लांट की स्थापना, चालू करने तथा परीक्षण करने के लिए परामर्शी सेवा देना; मेसर्स एससीसीएल के एमएनजी क्षेत्र में ईपीसी मोड पर पीके ओसी में 10 एमटीपीए कन्वेयर स्ट्रीम की स्थापना के लिए परामर्शी सेवा; मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के केरेनडारी कोयला खनन परियोजना के विभिन्न सर्वेक्षण कार्य करने के लिए बाहरी एजेंसी की नियुक्ति, आदि ।

- गैर सीआईएल तथा सीआईएल क्षेत्र के लिए सीएमपीडीआई के गवेषण कार्यक्रम में 951 ब्लॉक शामिल है। कोयला मंत्रालय के निदेशानुसार सीएमपीडीआई में सीबीडीएमएस (कोल ब्लॉक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम) नामक एक पोर्टल विकसित किया गया है जिसमें 'ब्लॉकों में वर्तमान परियोजनाएँ/चालू खदानें', 'प्रत्येक ब्लॉक में निष्कासित कोयले की मात्रा तथा शेष भंडार', 'प्रत्येक ब्लॉक में क्षेत्र (सीमा) सहित गवेषण की वर्तमान स्थिति', 'प्रत्येक ब्लॉक

में अब तक किए गए खर्च' आदि विशेषताएं शामिल हैं। उपरोक्त पोर्टल से कोयला क्षेत्र की रणनीतिक योजना पर नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलने की उम्मीद है ।

- क्यूपीआर परियोजनाओं, एफएमसी परियोजनाओं, सीआईएल अनुबंधों और अन्य परियोजनाओं की निगरानी के बारे में डैशबोर्ड के निर्माण के लिए ऑनलाइन एमएस प्रोजेक्ट सर्वर स्थापित किया गया है। मास्टर कंट्रोल नेटवर्क की स्थापना का उद्देश्य सीआईएल परियोजनाओं में गतिविधियों, कार्यों, संसाधनों और लागत बाधाओं की निगरानी करना है। विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए पावर-बीआई का उपयोग करके वर्गीकृत डैशबोर्ड बनाया गया है जो संसाधन व्यक्तियों को विभिन्न समयबद्ध गतिविधियों तथा अलार्म के साथ स्लिपेज को प्रदर्शित करता है।

- अनुषंगी कम्पनी के कर्मचारियों/उपभोक्ताओं/विक्रेताओं द्वारा मुद्दों को दर्ज करने के लिए सीएमपीडीआई द्वारा एक एकीकृत मोबाइल ऐप "**सीआईएल संवाद**" विकसित किया गया है। यह ऐप उपयोगकर्ता अनुकूल है और सभी स्टेक होल्डरों (हितधारकों) के लिए खुला है। विभिन्न फैकल्टी के कर्मचारियों वाली एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम ऐप में उठाए गए मुद्दों के जल्द-से-जल्द निवारण के लिए लगातार निगरानी कर रही है।

- सीआईएल की अनुषंगियों में संवेदनशील स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए सीएमपीडीआई द्वारा एक एकीकृत मोबाइल ऐप "**सीआईएल आई**" विकसित किया गया है।

- सीएमपीडीआई के कॉलोनियों के व्यापक रखरखाव के लिए क्वार्टर शिकायत प्रणाली (https://estate.cmpdi.co.in) पोर्टल विकसित किया गया है।

- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नवम्बर, 2020 में कोकिंग कोल मिशन पर एक कार्यदल का गठन किया गया था। सीएमपीडीआई द्वारा "सीआईएल ब्लॉकों में कोकिंग कोल पर रिपोर्ट, दिसम्बर, 2020" तैयार की गयी थी और 23.12.2020 को सचिव (कोयला) के समक्ष इसका प्रेजेंटेशन दिया गया। सीआईएल को देश में कोकिंग कोल उत्पादन और वाशरी के संवर्द्धन पर एक रणनीति पत्र तैयार करने के लिए कहा गया था और इसे तैयार कर एमओसी को प्रस्तुत करने के लिए सीआईएल को प्रस्तुत कर दिया गया।

- सीएमपीडीआई तथा खान और भूविज्ञान विभाग, झारखण्ड सरकार के बीच 8 फरवरी, 2021 को रांची में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया । यह एमओयू झारखंड के भीतर खनिज ब्लॉकों की पहचान, अन्वेषण और विकास के लिए विभिन्न संभावित अवसरों की खोज में सहायता करने के लिए सीएमपीडीआई को शामिल करने के लिए किया गया है। यह एमओयू 3 साल की अवधि के लिए होगा जिसे दोनों पक्षों की लिखित सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

- सीएमपीडीआई तथा भूविज्ञान और खनन विभाग (डीजीएम), अरूणाचल प्रदेश के बीच 25 फरवरी, 2021 को इटानगर, अरूणाचल प्रदेश में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया । यह एमओयू अरूणाचल प्रदेश राज्य के कोयला और गैर-कोयला खनिजों के लिए

अन्वेषण और संबद्ध गतिविधियों को शुरू करने के लिए सीएमपीडीआई को शामिल करने के लिए किया गया है। यह समझौता ज्ञापन 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा और दोनों पक्षों की लिखित सहमति पर पारस्परिक रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है।

- सीएमपीडीआई मुख्यालय, रांची के सीएसआर के तहत ''रांची जिले के गांवों के 40 लाभार्थियों को सीआईपीईटी के माध्यम से प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने'' के लिए सीएमपीडीआई एवं सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोललॉजी (सीआईपीईटी), सीएसटीएस, रांची के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- सीआईएल क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में भारत में सीबीएम विकास में तेजी लाने के लिए तरीके और तकनीक, सीबीएम वर्गीकरण और अन्य संबंधित मुद्दों पर सीबीएम क्षेत्र में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों के अनुभवों को साझा और चर्चा करने हेतु सीएमपीडीआई ने कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में कोल इंडिया लिमिटेड और यूएस ईपीए के सहयोग से "सीबीएम रिसोर्स-रिजर्व असेसमेंट" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया।
- सीएमपीडीआई, आरआई-4 कॉलोनी परिसर में एमबीबीआर तकनीक से युक्त 100 केएलडी एसटीपी सफलतापूर्वक चालू है और लगभग 75 केएल प्रतिदिन उपचारित पानी का कॉलोनी परिसर में बागवानी और अन्य सफाई कार्यों के लिए पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। कॉलोनी परिसर के बाहर कोई भी गंदा पानी नहीं छोड़ा जाता है।
- एमसीएल के 125 भू-तकनीकी प्रकोष्ठ के अधिकारियों के लिए ढलान स्थिरता पर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- सीवीसी/सीआईएल/एमओसी/डीओपीटी/सीएमपीडीआई परिपत्रों और दिशानिर्देशों के संग्रह (कंपेडियम) की ई-बुक प्रकाशित की गयी।
- 2020-21 के दौरान दिए गए 21.20 करोड़ रूपए के कुल आपूर्ति आदेशों में से 9.64 करोड़ रूपए (कुल का 45.51%) के आपूर्ति आदेश एमएसई को दिए गए । एमएसई से खरीद का प्रतिशत कुल खरीद के 25 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य से काफी ऊपर है।
- गवेषण/सर्वेक्षण कार्य को सुदृढ़ करने के लिए सिस्मोग्राफ, डीजीपीएस, मैटलैब/सर्पैक/माइनेक्स सॉफ्टवेयर जैसे उपकरण / सॉफ्टवेयर के लिए आपूर्ति आदेश दे दिए गए हैं।
- गवेषण/सर्वेक्षण कार्य को सुदृढ़ करने के लिए सिस्मोग्राफ, डीजीपीएस, मैटलैब/सर्पैक/माइनेक्स सॉफ्टवेयर जैसे उपकरण सॉफ्टवेयर के लिए आपूर्ति आदेश दे दिए गए हैं।
- **सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी):** पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत यानी 4.648 करोड़ रूपये सांविधिक प्रावधान के लक्ष्य की तुलना में 4.69 करोड़ रूपये (अंतिम) का व्यय किया गया है।
- **सीएसआर के तहत कौशल विकास:** सीएसआर के तहत सिपेट के माध्यम से कुल 80 युवाओं को प्लास्टिक इंजीनियरिंग में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

- **इन-हाउस प्रशिक्षण:** विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी विषयों पर 500 कर्मचारियों के लक्ष्य के मुकाबले कुल 514 कर्मचारियों को इन-हाउस प्रशिक्षित किया गया है।
- **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण:** 2020-21 के दौरान, सीएमपीडीआई ने अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय संस्थान में ड्रिलिंग, मेकेनिकल, सिविल, कम्प्यूटर विज्ञान, खनन, आदि के विभिन्न विषयों में 166 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया ।